

 सत्यमेव जयते	<b>राजस्थान राज-पत्र</b> <b>विशेषांक</b>	<b>RAJASTHAN GAZETTE</b> <b>Extraordinary</b>
	साधिकार प्रकाशित	<i>Published by Authority</i>
	फाल्गुन 02, शुक्रवार, शाके 1946 - फरवरी 21, 2025 Phalguna 02, Friday, Saka 1946- February 21, 2025	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

**वित्त (वित्तीय नियम) विभाग**

अधिसूचना

**जयपुर, फरवरी 21, 2025**

**जी.एस.आर.33** :-राजस्थान राजभाषा अधिनियम, 1956(1956 का अधिनियम संख्या 47) की धारा 4 के परन्तुक के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.2(1)/एफडी/जीएण्डटी-एसपीएफसी/2017 दिनांक 19.09.2024 का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

**राज्यपाल के आदेश से,**

मनीष माथुर,

**संयुक्त शासन सचिव।**

**वित्त (वित्तीय नियम) विभाग**

अधिसूचना

**जयपुर, सितम्बर 19, 2024**

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 32 के साथ पठित राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 (2012 का अधिनियम सं. 21) की धारा 6 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार की सामाजिक-आर्थिक नीतियों, केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के विभागों और उद्यमों के संसाधनों और विशेषज्ञता के उपयोग और उपापन संस्थाओं के व्यक्तिशः बोलियों के आमंत्रण और प्रक्रिया में अपेक्षित समय, धन और प्रयासों की बचत के लिए यह आवश्यक है, इस विभाग की, समय-समय पर यथासंशोधित, अधिसूचना संख्यांक एफ.1(8)/एफडी/जीएफएण्डएआर/2011 दिनांक 04 सितम्बर, 2013 में इसके द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

**संशोधन**

उक्त अधिसूचना की सारणी में विद्यमान क्रम संख्यांक 64 और उसकी प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित नये क्रम संख्यांक 65 और 66 तथा उनकी प्रविष्टियां जोड़ी जायेंगी, अर्थात्:-

“

65.	समस्त प्रकार के सर्वेक्षण, जोनल योजनाएं, गुणवत्ता नियंत्रण	राजस्थान राज्य भू-संपदा विकास परिषद् (राजरेडको)	1. प्रत्येक मामले में 50.00 लाख रुपये तक का उपापन
-----	--	---	---

	परीक्षण, तृतीय पक्षकार निरीक्षण, परामर्श, डीपीआर बनाना और अन्य इंफ्रा संबंधी कार्य		2. उपापन का विनिश्चय निम्नलिखित से मिलकर बनने वाली समिति की सिफारिश पर लिया जायेगा, अर्थात्:- (i) संबंधित प्रशासनिक विभाग का प्रभारी सचिव - अध्यक्ष, (ii) संबंधित विभाग का विभागाध्यक्ष - सदस्य, और (iii) संबंधित विभाग का वरिष्ठतम लेखा अधिकारी - सदस्य सचिव। दरें निम्नलिखित से मिलकर बनने वाली समिति की सिफारिश पर वित्त विभाग द्वारा विनिश्चित की जायेंगी, अर्थात्:- (i) संबंधित प्रशासनिक विभाग का प्रभारी सचिव - अध्यक्ष, (ii) संबंधित विभाग का विभागाध्यक्ष- सदस्य, (iii) संयुक्त सचिव से अनिम्न रैंक का वित्त विभाग का प्रतिनिधि - सदस्य, और (iv) संबंधित विभाग का वरिष्ठतम लेखा अधिकारी - सदस्य सचिव।
66.	ई-नीलाम प्लेटफार्म की सेवाएं	एनसीडीईएक्स लिमिटेड (एनईएमएल)/एमएसटीसी लिमिटेड	ई-मार्केट्स

”

[एफ.2(1)एफडी/एसपीएफसी/2017]

राज्यपाल के आदेश से,

मनीष माथुर,

संयुक्त शासन सचिव।